आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 31.07.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केन्द्र सरकार ने विशेष पूंजीगत सहायता के रूप में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत योजनाओं की पहली किश्त के तौर पर 380 करोड़ रुपये जारी किये।
- राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी; परिणाम घोषित होने के बाद विजयी जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- प्रदेश में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
- ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार में छद्मवेशधारी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी।

स्वीकृति

केन्द्र सरकार ने विशेष पूंजीगत सहायता के रूप में उत्तराखंड के लिए 615 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें पहली किश्त के तौर पर 380 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार इस दशक को उत्तराखंड के विकास का दशक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और केन्द्र से लगातार सहयोग मिल रहा है।

स्वीकृत धनराशि में राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, सौंग बांध पेयजल परियोजना, घाटों, बाईपास सड़कों और ड्रेनेज कार्य, पुलिस थानों व चौकियों के निर्माण, स्टार्टअप सुविधा, जलापूर्ति और सीवरेज योजनाएं तथा विद्युत पारेषण लाइनों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निर्माण, आईएसबीटी और आधुनिक कार्यशालाओं के निर्माण, डाकपत्थर बैराज एवं इच्छाड़ी बांध के मार्ग सुधार, तथा ऋषिकेश और देहरादून में पार्किंग, बाजार पुनर्विकास और विद्युत नेटवर्क भूमिगत करने की योजनाएं भी शामिल हैं।

मतगणना

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कुल 10 हजार 915 पदों के लिए मतगणना में 15 हजार 24 कार्मिक लगाए गए हैं, जबकि सुरक्षा के लिए 8 हजार 926 जवान तैनात रहेंगे। चुनाव में 34 हजार 151 उम्मीदवार मैदान में हैं।

आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों के 89 विकासखंडों में दो चरणों में हुए मतदान का औसत प्रतिशत 69 दशमलव एक–छह रहा।

आयोग ने कहा कि मतगणना भी मतदान की तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होगी। मतगणना की निगरानी प्रेक्षकों, जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी करेंगे। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है और परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि परिणाम घोषित होने के बाद विजयी जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी।

दीक्षांत समारोह

देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 2023 बैच के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थीयों का दीक्षांत समारोह हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने परिवीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र और पदक प्रदान किए। इस अवसर पर न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने अधिकारियों से कहा कि एक लोक सेवक के रूप में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी समय कानून का उल्लंघन न करें। उन्हें लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण होना चाहिए और लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए।
स्वर्ण पदक से सम्मानित कर्नाटक के प्रशिक्षु अधिकारी पृथ्वीराज ने खुशी जताते हुए भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर और ईमानदारी से काम करने की बात कही।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक जगमोहन शर्मा ने बताया कि 109 भारतीय वन सेवा और भूटान के दो विदेशी प्रशिक्षुओं सहित 111 प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूरा किया।

सफल उड़ान

भारत और अमरीका ने कल अपने पहले अंतरिक्ष सहयोग की शुरुआत श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से जीएसएलवी रॉकेट की सफल उड़ान के साथ की। इसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह –निसार को विधिपूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। निसार को इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। इसरो के प्रमुख डॉ. वी. नारायण ने कहा कि जीएसएलवी ने निसार को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है।

शैक्षणिक मानक सुनिश्चित

प्रदेश में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण–एस०एस०एस०ए का गठन किया जाएगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इसके शीघ्र गठन के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर रावत ने कहा कि एस०एस०एस०ए से स्कूलों की मान्यता, सीखने के लक्ष्य और कक्षा मानक तय होंगे, जिससे निजी और राजकीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि न्यूनतम आयु सीमा पूरी न करने वाले छात्र–छात्राओं को भविष्य में कक्षा–1 के बजाय बालवाटिका–3 में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए बालवाटिका–1 और 2 की तरह बालवाटिका–3 का संचालन प्रदेशभर के प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया जाएगा।

मंत्री ने नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप कक्षा–1 से 8 तक का पाठ्यक्रम तैयार न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दो माह में पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में करीब 150 क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत का मुद्दा भी उठाया गया। इसके लिए आपदा मद से लगभग 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी भी आपदा न्यूनीकरण मद से प्रति विद्यालय दो–दो लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए।

ऑपरेशन कालनेमि

मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी हरिद्वार में छद्मवेशधारी बाबाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार, प्रमेन्द्र डोबाल के नेतृत्व में जिले के शहर से देहात तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 44 बहरूपियों को हिरासत में लिया गया, जो साधु–संतों का भेष धरकर तंत्र–मंत्र, जादू–टोना और अन्य ढोंग कर श्रद्धालुओं को भ्रमित कर रहे थे।

पुलिस ने सभी का मौके पर सत्यापन किया और जिनके दस्तावेज़ व गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, उन्हें हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छद्मवेशधारियों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने और उनके बिजली व पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने यह कार्रवाई पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न होने पर की है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए है।

जस्टिस रवींद्र मैठाणी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने रायवाला से भोगपुर और कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी किनारे हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

व्यय वित्त समिति बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति एवं व्यय वित्त समिति की बैठक हुई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि घाटों के निर्माण में गुणवत्ता के साथ हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाए और अगस्त माह के अंत तक कुंभ 2027 की पूरी कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने सभी स्थायी और अस्थायी कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

कुंभ क्षेत्र के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट तत्काल कराने को कहा गया। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए पूरे क्षेत्र का सर्क्यूलेशन प्लान तैयार करने और पर्वों के दौरान अधिकतम भीड़ के अनुरूप प्रवेश–निकासी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कुंभ क्षेत्र और आसपास के रेलवे स्टेशनों की क्षमता विकास और सौंदर्यीकरण के लिए रेल मंत्रालय से समन्वय बनाने, अत्यधिक भीड़ के समय होल्डिंग एरिया बनाने और नए पार्किंग स्थलों की पहचान कर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी भूमि पर भी पार्किंग की व्यवस्था के लिए भूमि मालिकों से समय रहते बातचीत करने को भी कहा।

व्यय वित्त समिति में लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें हरिद्वार में सड़क चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण और ऊपरी गंगा नहर के किनारे घाट निर्माण कार्य शामिल हैं।